http://amritkalashtimes.com

अमृत कलश टाइम्स

वर्ष : 18
अंक : 113

प्रयागराज बुधवार 08 जनवरी 2025

पृष्ठः- 4, मूल्यः- एक रूपया

पीएम 26 जनवरी को कर सकते हैं जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन

श्रीनगर,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को गांदरबल में बनी जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे, जो कश्मीर की कनेक्टिविटी और सुरक्षा को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 जनवरी को गांदरबल में बनी जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने की संभावना है। यह सुरंग सेना और नागरिकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाली है।

● कनेक्टिविटी में आएगा नया मोड़

चीनी वायरस का संकट

योगी की फोर्स अलर्ट, सीएम की बैठक, कैसी है महाकुंभ की तैयारी

लखनऊ,(एजेंसी)। महाकुंभ में अब हफ्ते भर का वक्त बचा है। महाकुंभ में भी इस वायरस की एंट्री का खौफ सता रहा है। याद होगा कि कोरोना काल में पहला मरीज केरल में मिला और इसके 15 दिन के भीतर ही पूरे देश में वायरस का कोहराम मच गया। इस बार एचएमपीबी वायरस के केस मिलने के बाद कोई ये दावे से नहीं कह सकता कि ये तेजी से नहीं फैलेगा और प्रयागराज तक नहीं पहुंचेगा। वायरस का नाम सुनते ही कोविड काल की डरावनी यादें ताजा हो गई। शहरों का संपूर्ण लॉकडाउन, दुकानों के शटर डाउन, दफ्तरों पर ताले और घरों की बालकॉनी में कैद इंसान। अस्पताल में अपनों को खोने का दर्दनाक पल और शमशान घाट में शवों का रेला। हिंदुस्तान ने क्या क्या नहीं झेला। एक बार फिस से हिंदुस्तान में एचएमपीबी वायरस केस आने से हड़कंप मच गया है। चीन के वुहान से फैले इस वायरस का संक्रमण बेंगलुरु और अहमदाबाद के बाद नागपुर में भी देखने को मिला है।

इस वायरस की हिंदुस्तान में घुसपैठ बेहद गलत वक्त पर हुई है। महाकुंभ में अब हफ्ते भर का वक्त बचा है। महाकुंभ में भी इस वायरस की एंट्री का खौफ सता रहा है। याद होगा कि कोरोना काल में पहला मरीज केरल में मिला और इसके 15 दिन के भीतर ही पूरे देश में वायरस का कोहराम मच गया। इस बार एचएमपीबी वायरस के केस मिलने के बाद कोई ये दावे से नहीं कह सकता कि ये तेजी से नहीं फैलेगा और प्रयागराज तक नहीं पहुंचेगा। एचएमपीवी वायरस पर योगी की बैठक इस वायरस के खतरे को देखते हुए महाकुंभ में भी बड़ी तैयारी की गई है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। नए वायरस को लेकर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आपात बैठक बुलाई है। वह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

● एचएमपीवी वायरस पर योगी की बैठक
● समाजवादी सांसद ने सरकार से की अपील
● महाकुंभ में चीन से आने वालों की एंट्री होगी बैन?

साधन से नहीं विचार से बड़ा बने– स्वामी अवधेशानन्द गिरि जी महाराज

महाकुंभ नगर। झूंसी सेक्टर अठारह अन्नपूर्णा मार्ग में स्थित प्रभु प्रेमी संघ कुम्भ शिविर में जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि जी महाराज ने श्रीमद्भागवत कथा के दिव्य आध्यात्मिक अनुष्ठान के द्वितीय दिवस में कहा कि पहला तप आहार की शुचिता है। आहार शुद्धि से ही विचार और व्यवहार में शुद्धता आती है। श्रेष्ठ संकल्प की संसिद्धि में आहार, निहार और विचारों का नियमन आवश्यक है, इसलिए साधनों से नही विचारों से बड़ा बनिए। कथा का प्रयोजन ब्रह्मरस की निष्पत्ति है। इसलिए महापुरुषों का कहना है कि कथा सुनी नही जाती, कथा पी जाती है। पेयम पेयम श्रवण पुटके ..और कथा श्रवण के लिए हमारे कान समुद्र की तरह विशाल होने चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश के लिए पहला संस्कार भी श्रवण ही है। जैसे सलिलाएँ–सरोवर सागर की ओर जाने के लिए लालायित रहती हैं, नदियाँ शताब्दियों से सागर की तरफ जा रही है, लेकिन सागर में जल का कहीं अतिरेक नही होता है। हमारे अन्दर सद्–प्रवृत्तियाँ तब जगेंगी, जब हम अच्छे लोगों का संग करेंगे। मनुष्य और किसी से नहीं हारता, वह अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण ही पराभूत होता है। यह युग संचयन का युग है, संग्रहण–भंडारण और भौतिकीय प्रभाव की महत्ता का युग है। यदि हमारा आहार, विहार, निहार, विचार, संस्कार, व्यवहार और सदाचार ठीक है तो हमारा जीवन सुन्दर, व्यवस्थित और अनुशासित हो जायेगा। परीक्षित का आशय है – जो परा–शक्तियों से अभिरक्षित है अथवा जिसकी चिरकाल से प्रतीक्षा की गई हो। सृष्टि के आरम्भ की कथा में मनु–शतरूपा तथा ऋषि कर्दम–देवहूति संवाद सुनाते हुए। सृष्टि के क्रम में कन्या पहले आई। इसलिए यदि आपके घर में कन्या जन्में तो उत्सव मनाएँ। भगवान कपिल के जन्म, उनके द्वारा उपदेशित सांख्य योग के विवेचन के अनन्तर द्वितीय दिवस की कथा सम्पन्न हुई।

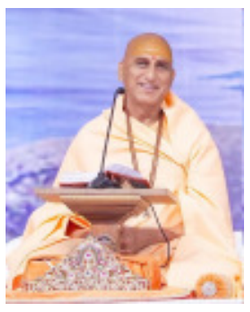

कांग्रेस की रात्रिभोज में शिवकुमार की अनुपस्थिति से नेतृत्व को लेकर अटकलें तेज

बेंगलुरु,(एजेंसी)। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की ओर से आयोज 02 जनवरी की रात्रिभोज को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। श्री सिद्दारमैया के करीबी सहयोगी लोक निर्माण मंत्री सतीश जरकीहोली के निवास पर 02 जनवरी को इस भोज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी, एसटी)और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों के कई मंत्री शामिल थे, जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जनाधार के मुख्य स्तंभ हैं। आधिकारिक तौर पर इस एक अनौपचारिक भोज बताया गया, लेकिन सियासी गलियारे में इस बैठक को उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। श्री शिवकुमार पारिवारिक छुट्टी पर तुर्की में होने के कारण इस भोज में शामिल नहीं हुए थे। दो जनवरी को हुई इस बैठक के तुरंत बाद सिद्दारमैया ने संवाददाताओं से कहा था, ष्यह राजनीतिक महत्व की बैठक नहीं थी।ष इस बीच, विपक्ष के नेता आर. अशोक ने दावा किया है कि कांग्रेस विधायकों के बीच आंतरिक असंतोष के कारण सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के कई असंतुष्ट विधायक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संपर्क में हैं। उन्होंने प्रशासनिक विफलताओं के लिए भी कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि दूध उत्पादकों को बकाया राशि और एम्बुलेंस चालकों को वेतन देने में नहीं मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह श्री सिद्दारमैया के कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर के आवास पर श्री सिद्दारमैया के खेमे ने इसी तरह से भोज का आयोजन था।

मंथन का विषय

हर सेवा से पैसा कमाने का चलन अब मरीज की मजबूरी से फायदा उठाने तक पहुंच गया है। मांग एवं सप्लाई के सिद्धांत यहां भी लागू होना समाज की कैसी सूरत को जाहिर करता है, यह हम सबके लिए आत्म–मंथन का विषय है।

तो अब यह चलन इलाज में पहुंच गया। बड़े प्राइवेट अस्पताल अब सर्जरी या बेड की प्राथमिकता मरीजों की जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि इस हिसाब से तय कर रहे हैं कि उनमें से कौन ज्यादा पैसा देगा। मतलब यह कि अस्पताल में पहले से ज्यादा मरीज भर्ती हों, तो नए मरीज को इलाज के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे विमान या ट्रेन यात्रा में देना पड़ता है। जैसे–जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती है, टिकट महंगे होते जाते हैं। यही तरीका अब अनेक अस्पताल अपना रहे हैं। इस बारे में आई छपी एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ सेक्टर में यह नया चलन देखने को मिल रहा है। इससे मरीजों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मरीजों के साथ–साथ मेडिकल बीमा कंपनियों को बढ़ी हुई लागत उठानी पड़ रही है।

खबर है कि बीमा कंपनियां इस सूरत को ध्यान में रख कर पॉलिसी प्रीमियम बढ़ाने जा रही हैं। बीमा कंपनियों के मुताबिक इलाज का खर्च साल–दर–साल बढ़ रहा है। इलाज खर्च सामान्य महंगाई की दर के मुकाबले 14 फीसदी से ज्यादा बढ़ा है। वैसे में अस्पताल सर्ज प्राइस के ताजा नियम से इलाज और महंगा बना रहे हैं। नए नियम के कारण इलाज खर्च में करीब 20 फीसदी की तेजी आई है। यहां तक कि अब रुटीन इलाज में भी अस्पताल नया नियम लागू करने लगे हैं। यानी इनमें भी पीक चार्ज लागू हो रहा है। जानकारों के मुताबिक अस्पतालों ने सिर्फ सर्ज प्राइस का नया नियम ही लागू नहीं किया है। बल्कि वे कई नए तरीके अपना रहे हैं, जिससे इलाज महंगा होता रहा है।

मसलन, पहले एंजियोप्लास्टी अस्पताल एक पैकेज के रूप में करते थे। इसमें एंजियोग्राम और स्टेंटिंग को एक ही कीमत में शामिल किया जाता था। लेकिन अब कई अस्पताल इसके लिए वे अलग–अलग फीस वसूल रहे हैं। सार यह कि हर सेवा से पैसा कमाने का चलन अब मरीज की मजबूरी से फायदा उठाने तक पहुंच गया है। मांग एवं सप्लाई के सिद्धांत यहां भी लागू होना समाज की कैसी सूरत को जाहिर करता है, यह हम सबके लिए आत्म–मंथन का विषय है।

हरित प्रथाओं को प्रोत्साहित करने की रूपरेखा'

अशोक कुमार, – 'सौरभ दिद्दी, – 'सौरभ दिद्दी,

भारत ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने और अपने महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, दो आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के भविष्य को आकार देंगे। ये अनुपालन व्यवस्था के लिए विस्तृत प्रक्रिया और मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों के लिए मान्यता प्रक्रिया और पात्रता मानदंड हैं। आशा है कि वे मिलकर कार्बन उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित करने और कार्बन क्रेडिट के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के भारत के प्रयासों को उत्प्रेरित करेंगे, जिससे देश अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को अपनाएगा।

भारत की जलवायु रणनीति, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में उल्लिखित है। भारत ने न केवल इसे पूरा किया है बल्कि अपने कई लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया है। वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित, पेरिस समझौते का उद्देश्य सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना था। भारत ने शुरू में वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33–35 प्रतिशत तक कम करने का वादा किया था। हालाँकि, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए इस लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लिया। अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए, 2021 में ग्लासगो में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी–26) में, भारत ने और भी अधिक आक्रामक लक्ष्य निर्धारित किए। इसने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने, वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और उसी समय सीमा के भीतर गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी 50 प्रतिशत बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां तय समय से पहले ही हासिल करके, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास में नेतृत्व का प्रदर्शन किया है।

लेकिन हम वहां कैसे पहुंचे? यहीं पर भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) आता है। विचार सरल हैरू यदि कोई कंपनी अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करती है, तो वह कार्बन क्रेडिट नामक कुछ अर्जित करती है, जिसे वह अन्य कंपनियों को बेच सकती है जो अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह एक पुरस्कार प्रणाली की तरह है – जो कंपनियाँ पर्यावरण के लिए बेहतर काम करती हैं वे पैसा कमा सकती हैं, जबकि जिन्हें सुधार के लिए अधिक समय की आवश्यकता है वे अपने अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई के लिए क्रेडिट खरीद सकती हैं।

भारतीय कार्बन बाजार को एक व्यापक और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास को गति देते हुए डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा दे सके। भारतीय कार्बन बाजार, उत्सर्जन मूल्य निर्धारण पर बल देने के साथ, इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रस्तुत करता है। कंपनियों को कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमति देकर, भारत का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों को अपने कार्बन उत्सर्जन को सक्रिय रूप से कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश को लागत प्रभावी और बडे पैमाने पर डीकार्बोनाइज करने में सक्षम बनाया जा सके।

भारतीय कार्बन बाजार ढांचे का निर्माण

भारतीय कार्बन बाजार की नींव वर्ष 2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन के साथ रखी गई थी, जिसने सरकार को कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (सीसीटीएस) स्थापित करने का अधिकार दिया। यह योजना भारत को वैश्विक कार्बन बाजार प्रथाओं के साथ जोड कर कार्बन व्यापार को संचालित करने के लिए आवश्यक नियामक संरचना प्रदान करती है। सीसीटीएस, जून 2023 में पेश किया गया और दिसंबर 2023 में और संशोधित किया गया, जो दो प्रमुख व्यवस्थाओंरू अनुपालन और ऑफसेट के माध्यम से कार्बन व्यापार के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अनुपालन व्यवस्था उन उद्योगों और क्षेत्रों को लक्षित करता है जिन्हें ष्बाध्य संस्थाओंष् के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन संस्थाओं को सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है। यदि कोई बाध्य इकाई अपने उत्सर्जन को निर्धारित लक्ष्य से कम कर देती है, तो उसे कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जिसका ट्रेडिंग एक्सचेंज पर कारोबार किया जा सकता है। इसके विपरीत, जो संस्थाएँ अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहती हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई के लिए क्रेडिट खरीदना होगा। यह बाजार–संचालित व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कंपनियों को उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे यह भारत के लिए अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक आवश्यक उपकरण बन सके।

ऑफसेट व्यवस्था गैर–बाध्यकृत संस्थाओं को कार्बन बाजार में स्वेच्छा से भाग लेने की अनुमति देकर अनुपालन प्रणाली को पूरक करता है। ये संस्थाएं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं या उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से पहल शामिल हो सकती हैं, कार्बन क्रेडिट के लिए अपनी गतिविधियों को पंजीकृत कर सकती हैं। समग्र उत्सर्जन में कमी में योगदान देकर, इन परियोजनाओं को कार्बन क्रेडिट से सम्मानित किया जाता है जिसका व्यापार किया जा सकता है। इससे भारत के कार्बन बाजार में प्रतिभागियों के एक व्यापक नेटवर्क को प्रोत्साहन मिलता है।

'अनुपालन और सत्यापन का समर्थन करने के लिए नए दिशानिर्देश'

अनुपालन व्यवस्था की विस्तृत प्रक्रिया बताती है कि कार्बन बाजार प्रणाली कैसे काम करती है। यह कंपनियों को दिखाता है कि वे अपने उत्सर्जन स्तर की कैसे निगरानी और रिपोर्ट कर सकते हैं और यदि वे अपने उत्सर्जन–कटौती लक्ष्यों को पूरा करते हैं या पूरा करते हैं तो वे कार्बन क्रेडिट कैसे अर्जित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सीमेंट कंपनी अपने उत्सर्जन को

आवश्यकता से अधिक कम कर देती है, तो वह अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकती है। ये क्रेडिट उन बिंदुओं की तरह हैं जिन्हें कंपनी किसी अन्य व्यवसाय, संभवतरू इस्पात कारखाने को बेच सकती है, जिसके लिए उत्सर्जन कम करना कठिन हो रहा है। इस तरह, जिन व्यवसायों को उत्सर्जन में कटौती के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, वे अब भी बेहतर प्रदर्शन करने वालों से क्रेडिट खरीदकर अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं।

अनुपालन व्यवस्था की यह विस्तृत प्रक्रिया, अनुपालन प्रक्रिया के लिए कैसे काम करेगी, इसके लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। यह दस्तावेज उन सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और समय–सीमाओं की रूपरेखा तैयार करता है जिनका हितधारकों को अपने उत्सर्जन कटौती दायित्वों को पूरा करने के लिए पालन करना चाहिए। इसमें यह मार्गदर्शन शामिल है कि संस्थाओं को अपने ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की निगरानी, ??रिपोर्ट और सत्यापन कैसे करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह है।

दूसरा दिशानिर्देश, जिसे प्रत्यायन प्रक्रिया कहा जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि उत्सर्जन में कटौती वास्तविक है या नहीं, और इसकी जांच करने वाली कंपनियां भरोसेमंद और सक्षम हैं। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या व्यवसाय ईमानदारी से अपने उत्सर्जन स्तर की रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियां ??(एसीवी) तीसरे पक्ष के संगठन होंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई उद्योग अधिक ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी या नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्सर्जन को कम करने का दावा करता है, तो एसीवी किसी भी कार्बन क्रेडिट देने से पहले संख्याओं की दोबारा जांच करेगा। यह ऐसे लेखा परीक्षक होने जैसा है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सटीक और निष्पक्ष हो। यह सुनिश्चित करता है कि प्रणाली पारदर्शी है, और हम भरोसा कर सकते हैं कि उत्सर्जन में कटौती वास्तविक है, न कि केवल कागज पर।

यह बेहतर ढंग से समझने के लिए कि यह प्रणाली व्यवहार में कैसी दिख सकती है, आइए कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरणों पर विचार करेंरू भारत में एक बड़ी इस्पात कंपनी को वर्ष के अंत तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 10 प्रतिशत तक कम करना होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कंपनी अपनी मशीनरी को अधिक ऊर्जा–दक्ष बनाने के लिए अपग्रेड करती है, जिससे उसका कार्बन उत्सर्जन 15 प्रतिशत कम हो जाता है। इन उत्सर्जन की जाँच और सत्यापन मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अतिरिक्त 5 प्रतिशत कटौती से कंपनी को कार्बन क्रेडिट मिलता है जिसे वह सीमेंट निर्माता जैसी किसी अन्य कंपनी को बेच सकती है, जो अपने उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस तरह, दोनों कंपनियों को लाभ होता है जबकि भारत का समग्र उत्सर्जन कम हो जाता है।

'भारतीय कार्बन बाजार के लिए भविष्य में आगे क्या होगा?'

भारतीय कार्बन बाजार का संचालन अब भी शुरुआती चरण में है, लेकिन जमीनी कार्य तेजी से आकार ले रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), जो आईसीएम के प्रशासक के रूप में कार्य करता है, वर्तमान में अनुपालन व्यवस्था में भाग लेने वाले उद्योगों के लिए क्षेत्र–विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्यों को अंतिम रूप दे रहा है। ये लक्ष्य भारत के एनडीसी के अनुरूप उत्सर्जन में कटौती हासिल करने की दिशा में कंपनियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण होंगे।

साथ ही, बीईई एक आईसीएम पोर्टल विकसित करने पर भी काम कर रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यह कार्बन क्रेडिट के सुचारू व्यापार को सक्षम करेगा। यह आईटी अवसंरचना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी कि कार्बन बाजार कुशलतापूर्वक चले और लेनदेन सभी प्रतिभागियों के लिए पारदर्शी और सुलभ हो। इसके अतिरिक्त, बीईई कार्बन क्रेडिट के व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को विकसित करने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के साथ सहयोग कर रहा है, जिससे भारत के कार्बन बाजार के ढांचे को और मजबूत किया जा सके।भारतीय कार्बन बाजार एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करने के लिए तैयार है, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा। व्यवसायों को अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रेरित करने और सफल होने वालों को पुरस्कृत करके, बाजार हरित प्रौद्योगिकियों की ओर बदलाव में तेजी लाता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कंपनियां अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की दिशा में अधिक लागत प्रभावी तरीके से काम कर सकें। समय के साथ, जैसे–जैसे अधिक उद्योग भाग लेंगे, कार्बन बाजार व्यवसायों को कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमति देकर कार्बन उत्सर्जन में कटौती की लागत को कम करने में सहायता करेगा। यह व्यापार उन कंपनियों को सक्षम बनाता है जिन्हें अपने उत्सर्जन को कम करना चुनौतीपूर्ण या महंगा लगता है, ताकि वे पहले से ही स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अग्रणी लोगों से क्रेडिट खरीद सकें।संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुत्तरश ने कार्बन बाजारों के महत्व पर बल देते हुए कहा, ष्हमें कार्बन उत्सर्जन अंतर को कम करने की आवश्यकता है और कार्बन बाजार उस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं, जो स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में निवेश को प्रोत्साहन दे सकते हैं।ष् यह रेखांकित करता है कि कार्बन बाजार व्यवसायों और व्यक्तियों को उनके संचालन और प्रथाओं में सार्थक परिवर्तन में योगदान करने के लिए कैसे सशक्त बनाता है।

एक बाजार बनाने से जहां कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है, व्यवसायों के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की लागत अधिक प्रबंधनीय हो जाती है। प्रत्येक कंपनी स्थायी परिचालन में परिवर्तन का पूरा खर्च वहन करने के बजाय, प्रतिस्पर्धी बने रहते हुए धीरे–धीरे बदलाव ला सकती है। भारतीय कार्बन बाजार एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करता है, जिसमें वर्ष 2030 तक 15 अरब डॉलर का बाजार बनने की क्षमता है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकियों और कम कार्बन नवाचारों में महत्वपूर्ण निवेश होगा। कार्बन डाइ ऑक्साइड के तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में, भारत का कार्बन बाजार वैश्विक उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे देश को वर्श 2070 तक अपने महत्वाकांक्षी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह दृष्टिकोण न केवल अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में भारत की यात्रा को तेज करता है बल्कि व्यवसाय डीकार्बोनाइजेशन के वित्तीय बोझ को कम करने में सहायता भी करता है। अंततरू, भारतीय कार्बन बाजार भविष्य के लिए एक स्थायी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाधान का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे धरती और अर्थव्यवस्था, दोनों को लाभ होता है।

रोशनी में रैंकिंग्स का सच–झूठ

मोदी सरकार को विश्वसनीय आंकड़ों से खास गुरेज है। दशकीय जनगणना तक उसकी प्राथमिकता में नहीं है, तो आंकड़ों के प्रति उसके अपमान भाव को सहज ही समझा जा सकता है। जबकि ऐसे आंकड़े सामने हों, तो रैंकिंग्स का सच–झूठ खुद जाहिर हो जाएगा।

पिछले हफ्ते ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ। हर साल की तरह भारत में यह राजनीतिक विवाद का मुद्दा बना। हालांकि इस बार भारत की रैंकिंग में कुछ सुधार दिखा– भारत 111वें से 105वें स्थान पर चला आया– मगर यह रैंक भी बहुत नीचे है, इसलिए यह इंडेक्स नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का फिर से औजार बना। मोदी सरकार का नजरिया ऐसी रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर देने का रहा है। सरकार ऐसे सूचकांकों के लिए आंकड़े इकट्ठे करने के तरीके पर सवाल खड़े करती है। जबकि ऐसा नहीं है कि उसे ऐसे हर इंडेक्स से गुरेज हो। जिन रैंकिंग्स में भारत की बेहतर सूरत दिखे, उसका इस सरकार द्वारा धुआंधार प्रचार भी किया जाता है। अपने आरंभिक वर्षों में विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का दर्जा उछलने को उसने अपनी खास उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया था।

लेकिन जल्द ही विशेषज्ञों ने उस सूचकांक की खामियां स्पष्ट कर दीं। भारत सहित कई देशों पर उसे को सुनियोजित ढंग से प्रभावित करने के आरोप लगे। विवाद इतना बढ़ा कि विश्व बैंक ने वह सूचकांक तैयार करना ही छोड़ दिया। उधर गुजरे दस साल में मानव विकास एवं लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं संबंधी तमाम सूचकांकों पर भारत की बदतर तस्वीर उभरी है। वैसे विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कई सूचकांक गहन शोध पर आधारित नहीं होते। वे फैलते गए एनजीओ कल्चर का हिस्सा हैं। फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एनजीओ इन्हें हर साल जल्दबाजी में तैयार कर देते हैं।

मगर हकीकत यह भी है कि इन सूचकांकों को दुनिया भर के मीडिया में खूब प्रचार मिलता है। देशों की छवि इनसे बनती बिगड़ती है। तो हल क्या है? समाधान यह है कि भारत अपने हर क्षेत्र के बारे में विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़े खुद जारी करे। मगर मोदी सरकार को ऐसे आंकड़ों से खास गुरेज रहा है। दशकीय जनगणना तक उसकी प्राथमिकता में नहीं है, तो विश्वसनीय आंकड़ों के प्रति उसके अपमान भाव को सहज ही समझा जा सकता है। जबकि ऐसे आंकड़े सामने हों, तो उनकी रोशनी में रैंकिंग्स का सच–झूठ खुद जाहिर हो जाएगा।

खाद्यान्नों की महंगाई नहीं रुक रही!

अजीत द्विवेदी

एक बार फिर सरकार की ओर से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी हुए हैं और एक बार फिर कहा गया है कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। जब भी महंगाई दर बढ़ती है तो लगभग हर बार यही कारण होता है कि खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। इस बार जो आंकड़ा आया है यानी सितंबर, 2024 का उसमें कहा गया है कि खाने पीने की महंगाई दर 5.66 फीसदी से बढ़ कर 9.24 फीसदी हो गई। इसी वजह से सितंबर महीने की खुदरा महंगाई दर अगस्त के 3.65 फीसदी से बढ़ कर 5.49 फीसदी हो गई।

जाहिर है अगस्त में भी खुदरा मंहगाई दर बढने में खाद्यान्नों की महंगाई का ही हाथ था क्योंकि महंगाई दर के आकलन में खाने पीने की चीजों का हिस्सा 50 फीसदी होता है। बहरहाल, सितंबर में तो खाने पीने की चीजों की कीमतों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। खाने पीने की चीजों की महंगाई 9.24 फीसदी यानी दहाई के करीब पहुंच गई। इसमें सबसे ज्यादा महंगाई सब्जियों की कीमत में दिखी, जो अगस्त के 11 फीसदी से बढ़ कर सितंबर में 36 फीसदी पहुंच गई। सोचें, सितंबर के महीने में सब्जियों की कीमत 36 फीसदी बढ़ी है! सितंबर में महंगाई दर मासिक आधार पर करीब दो फीसदी और सालाना आधार पर करीब एक फीसदी ज्यादा रही है।

इस आंकड़े से सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह ये है कि क्या खाने पीने की चीजों का उत्पादन कम हो रहा है या उनकी आपूर्ति शृंखला में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से इन वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है? ध्यान रहे अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि मांग और आपूर्ति में अंतर से कीमतें घटती या बढ़ती हैं। मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा तो कीमत कम होगी और अगर आपूर्ति कम है तो कीमत बढ़ेगी। लेकिन खाने पीने की चीजों के मामले में इसका उलटा हो रहा है। देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। खाने पीने की हर चीज का उत्पादन बढ़ रहा है। इसके बावजूद कीमतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि आपूर्ति शृंखला में कहीं न कहीं गड़बड़ी है या जमाखोरी के जरिए कृत्रिम तरीके से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।

अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ा संकट है और इससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। सरकार को जग जाना चाहिए और इसे तत्काल रोकने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कृत्रिम तरीके से कीमतें बढ़ती हैं तो किसान और आम उपभोक्ता दोनों घाटे में रहते हैं और बिचौलिए या जमाखोरों को फायदा होता है। अगर कीमतें काबू में नहीं आती हैं तो केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों में कटौती संभव नहीं हो पाती है और ऊंची ब्याज दर का असर विकास दर पर होता है। इसका मतलब है कि कृत्रिम महंगाई किसान, उपभोक्ता और देश की अर्थव्यवस्था तीनों के लिए ठीक नहीं है।

कृत्रिम महंगाई को लेकर सबसे पहले सब्जियों की ही बात करें तो यह सही है कि इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है लेकिन कहीं भी बारिश से फसल बरबाद होने की खबर नहीं आई है। फिर भी सितंबर में सब्जियों की महंगाई 36 फीसदी बढ़ी है। इस आंकड़े की बारीकी में जाएं तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा महंगाई प्याज और टमाटर की बढ़ी है। प्याज और टमाटर दोनों की कीमत 78 फीसदी की दर से बढ़ी है। यानी सब्जियों की महंगाई जिस दर से बढ़ी है उससे दोगुनी दर से प्याज और टमाटर की कीमत बढ़ी है। सब्जियों की थोक महंगाई भी लगभग 50 फीसदी की दर से बढ़ी है। जब फसल बरबाद नहीं हुई और उत्पादन कम नहीं हुआ तो आखिर इनकी कीमतों में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई? ध्यान रहे सरकार का

अपना आंकड़ा है कि पिछले एक दशक से आलू, प्याज और टमाटर इन तीनों सब्जियों का उत्पादन भारत में रिकॉर्ड दर से बढ़ रहा है। प्याज के उत्पादन में तो चीन को पीछे छोड़ कर भारत पहले नंबर पर आ गया है और आलू व टमाटर के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। फिर भी इनकी कीमत कम नहीं हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के लोग पहले से ज्यादा आलू, प्याज और टमाटर खाने लगे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लोगों के मासिक खर्च में सब्जियों का हिस्सा पिछले एक दशक से तीन से चार फीसदी पर ही स्थिर है। जहां तक निर्यात की बात है तो भारत में आलू और टमाटर का जितना उत्पादन होता है उसका महज दो फीसदी निर्यात होता है। प्याज का निर्यात जरूर थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन वह भी 10 फीसदी से कम ही है। इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ रहा है, घरेल खपत नहीं बढ़ रही है, निर्यात भी स्थिर है फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं!

ऐसा नहीं है कि यह स्थिति सिर्फ सब्जियों के मामले में है। दूसरे खाद्यान्नों में भी यही स्थिति है। गेहूं और धान की भी रिकॉर्ड पैदावार हो रही है लेकिन इनकी कीमतें भी कम नहीं हो रही हैं। इस साल 11.30 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल के 11 करोड़ टन से ज्यादा है। यह अलग बात है कि इस साल सरकारी खरीद कम रही। किसानों ने सरकार को गेहूं नहीं दिया तभी सरकार सिर्फ 266 लाख टन ही गेहूं खरीद सकी, जबकि लक्ष्य 320 लाख टन खरीद का था। सरकार के गोदाम में गेहूं कम आए इसका मतलब है कि बाजार में निजी कारोबारियों ने ज्यादा गेहूं खरीदा और उसका भंडारण किया और कृत्रिम तरीके से महंगाई बढ़ाई। सितंबर तक गेहूं की कीमतों में प्रति क्विंटल एक सौ रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और आटे की कीमत भी तीन से चार रुपए किलो तक बढ़ी है। इसका असर अगस्त में सभी ब्रांड के ब्रेड्स पर पड़ा और उनकी कीमतें बढ़ गईं।

अब इसी से जुड़ा यह अहम सवाल यह है कि खाने पीने और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो क्या इसका फायदा किसान को होता है? इसका जवाब पिछले ही दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि आलू, प्याज और टमाटर पर हम लोग यानी एक सामान्य उपभोक्ता जितना खर्च करता है उसका एक तिहाई हिस्सा यानी 33 फीसदी ही किसानों को मिलता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक लगभग इतना ही पैसा आढ़तिए यानी थोक व्यापारी ले जाते हैं। इसके बाद रेहड़ी, पटरी वाले या सब्जियों के खुदरा व्यापारियों को एक तिहाई हिस्सा मिलता है। सोचें, सुदामा पांडेय श्धूमलच्य की कविता पर! एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है, मैं पूछता हूं– यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। वह तीसरा थोक और खुदरा व्यापारी है, जिसकी जेब में सारे पैसे जा रहे हैं। किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिल रही है और उपभोक्ता के ऊपर खाने पीने की चीजों की महंगाई का बोझ भी बढ़ रहा है। इसे दुरुस्त करने के लिए तत्काल भंडारण की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी, बिचौलियों पर लगाम लगानी होगी और आपूर्ति शृंखला में सुधार करना होगा।

लोनी नदी के पुनरोद्धार कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करें

डीएम एवं सीडीओ ने ग्राम पंचायत खटवारा में लोनी नदी व मादामई में गुजवर झील का किया निरीक्षण,

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन एवं मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा ने लोनी नदी के उदगम स्थल पर अवैध अतिक्रमण होने के कारण अविरलता एवं निर्मलता न होने से विलुप्त होती जा रही नदियों के पुनरोद्धार हेतु मनरेगा योजना के अन्तर्गत नदियों के पुनरोद्धार/कायाकल्प कार्यक्रम का विकास खण्ड बिहार के ग्राम पंचायत खटवारा में लोनी नदी का निरीक्षण किया गया। लोनी नदी जिसका उदगम विकास खण्ड बाबागंज की ग्राम पंचायत गुजवर में स्थित गुजवर झील से है, गुजवर झील विकास खण्ड बाबागंज की ग्राम पंचायत गुजवर एवं पुरमईसुल्तानपुर तथा विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ की ग्राम पंचायत मादामई से घिरी हुई है। लोनी नदी जनपद की पांच विकास खण्डों क्रमशः बाबागंज, रामपुर संग्रामगढ़, बिहार, लालगंज एवं लक्ष्मणपुर के 35 ग्राम पंचायतों से होती हुई सई नदी में समाप्त होती है। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत खटवारा में लोनी नदी पर मनरेगा योजना के द्वारा कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर मौके पर उपस्थित डीसी मनरेगा अश्वनी सोनकर को निर्देशित किया कि नदी के पुनरोद्धार में ढाल का विशेष ध्यान रखा जाये तथा खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी को साइड सरफेस पर डाली जाये जिससे मिट्टी कटकर पुनः नदी में न आये, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 1000 मीटर के चैनेज पर लगभग 5 मीटर की बन्धी भी बनायी जाये जिससे वर्षा ऋतु के बाद भी नदी की तलहटी में पानी रह सके। उन्होने निर्देशित किया कि नियमित अनुश्रवण करते हुये अधिक से अधिक श्रमिकों को नियोजित कराकर नियमानुसार नदी का पुनरोद्धार का कार्य अविलम्ब पूर्ण करायें। लोनी नदी पुनरोद्धार कार्य को मनरेगा दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास किया जाये तथा लोनी नदी के तटों पर वृक्षारोपण कराया जाये। इसके उपरान्त जिलाधिकारी एवं मुख्य

विकास अधिकारी ने विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ के ग्राम पंचायत मादामई में गुजवर झील का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि मत्स्य पालन हेतु गुजवर झील पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है जिस पर जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा को निर्देशित किया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से वार्ता कर अतिक्रमण का हटवाया जाये।

डीएम ने तहसीलों में आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर किया जारी -प्रतापगढ़।

जिलाधिकारी संजीव रंजन ने तहसीलों में आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस माह जनवरी, फरवरी व मार्च 2025 का रोस्टर जारी कर दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 04 जनवरी को तहसील पट्टी, 18 जनवरी को लालगंज, 01 फरवरी को रानीगंज, 15 फरवरी को सदर, 01 मार्च को लालगंज व 15 मार्च 2025 को कुण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जायेगा। इसी प्रकार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में दिनांक 04 जनवरी को तहसील रानीगंज, 18 जनवरी को पट्टी, 01 फरवरी को सदर, 15 फरवरी को कुण्डा, 01 मार्च को लालगंज व 15 मार्च 2025 को रानीगंज में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जायेगा। इसके अलावा मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 04 जनवरी को तहसील कुण्डा, 18 जनवरी को रानीगंज, 01 फरवरी को पट्टी, 15 फरवरी को लालगंज, 01 मार्च को सदर व 15 मार्च 2025 को कुण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जायेगा। अन्य तहसीलों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जायेगा।

'किसान बोले, जबरदस्ती हुई तो होगा उग्र आंदोलन

मीरजापुर। भारतीय किसान यूनियन द्वारा रविवार को सदर तहसील के ग्राम धौरूपुर, भरूहना और राजपुर के किसानों की जमीन को आवास विकास प्राधिकरण द्वारा आवास विकास गृह स्थान परियोजना के लिए अधिग्रहण करने के संदर्भ में 2004 से किसानों को बार-बार नोटिस

➤ किसानों की पंचायत में गूंजी आवास विकास गृह स्थान परियोजना के अधिग्रहण की आवाज

दिया जा रहा है जिसका किसान पुरजोर विरोध करते हुए जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में ग्राम धौरूपुर प्राथमिक विद्यालय के पास हनुमान जी के मंदिर पर किसानों की पंचायत हुई। जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत अध्यक्ष पप्पू सिंह, संचालन बाबूलाल चौहान ने किया। पंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने कहा कि किसानों की जमीन लेकर पूंजी पतियों को बसाने की साजिश चल रही है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। कहा भाकियू किसानों के साथ हैं, किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव प्रहलाद सिंह ने किसानों से अपील की कहीं भी किसी भी पेपर पर आप लोग दस्तखत नहीं करेंगे, यह जमीन किसानों के जीविकोपार्जन के एकमात्र साधन है इससे फूलों की खेती, सब्जियों और बागवानी लगाकर किसान भरण पोषण करते हैं। पंचायत को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि लड़ाई सभी लोग संगठित होकर लड़े महिलाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है मातृशक्ति को बढ़ चढ़कर भागीदारी निभानी पड़ेगी। जिलाध्यक्ष कंचन सिंह फौजी ने किसानों से अपील के कि आप की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन लड़ेगी और किसी भी कीमत पर जमीन जाने नहीं देगी जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। पंचायत में जिला उपाध्यक्ष सुखनंदन दुबे, जिला कोषाध्यक्ष स्वामी दयाल सिंह, अमिताभ पांडे अध्यक्ष पूर्वांचल विकास परिषद, राजकुमार चौहान जिला पंचायत सदस्य, मंगल सिंह चौहान, विजय कुमार सिंह पटेल, रामवृक्ष सिंह तहसील अध्यक्ष चुनार, प्रकाश चौहान, कामेश्वर सिंह एडवोकेट, अरविंद कुमार त्रिवेदी, मंगल सिंह चौहान, राजकुमार शर्मा, मन्नालाल, बाबूलाल, लक्ष्मीना देवी, लालमनी देवी, रामवती देवी, मनी मनीता देवी, श्यामलती आशा देवी, गीता देवी, उर्मिला देवी, राजकुमारी लक्ष्मीना व सैकड़ो महिलाएं उपस्थित रहीं।

विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में शिक्षक व अभिभावकों का सहयोग जरूरी

राजापुर (चित्रकूट)। तहसील अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय बरद्वारा में गुरुवार को शिक्षक अभिभावक बैठक समाजसेवी कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों के सामूहिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन को लेकर चर्चा की। अभिभावक और शिक्षकों ने बच्चों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने का संकल्प लिया।समाजसेवी श्री सिंह ने कहा कि पश्चात्य सभ्यता के कारण आज भारतीय संस्कृति के मूलाधार विद्यार्थियों में नैतिकता संस्कार की शिक्षा देना अनिवार्य होना चाहिए। जिससे बालकों में भारतीय सभ्यता के प्रति जागृति के साथ व्यवहारिक जीवन में माता-पिता तथा समाज के प्रति नैतिकता का बोध हो। बालकृष्ण विश्वकर्मा ने कहा कि भारतीय समाज में छात्र-छात्राओं के जीवन को ढालने का कार्य प्रथम गुरु माता पिता का दायित्व बनता है। डबल इंजन की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लागू कर शिक्षा का स्तर बढ़ा रही है। गणेश दत्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक व उच्च विद्यालयों को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए। शिक्षक अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी के साथ करें। प्रधानाध्यापक राजवर्धन सिंह ने विद्यालय की उपलब्धियों के साथ आगामी योजनाओं से अभिभावकों को अवगत कराया।

संक्षेप

गरीब की ठंड की वजह से मृत्यु ना हो

सुल्तानपुर। शीतलहरी व सर्द हवाओ कड़कती ठंड को देखते हुए चौथे दिन भी बाटा गया कंबल स अमहट चौराहा अस्पताल रोड दीवानी चौराहा पंत स्टेडियम पयागीपुर जिला अस्पताल बस स्टॉप आदि जगहों पर शनिवार देर रात ठंड से परेशान गरीब असहाय निर्धन लोगों को शियाने हैदर ए कर्रार वेलफेयर एसोसिएशन ने देर रात इन जगहों पर सोए हुए लोगों के बीच पहुंचकर कंबल खाना पानी गर्म कपड़े वितरण किया।शियाने हैदर ए कर्रार वेलफेयर एसोसिएशन के नौजवानो का मिशन 03 से देखते हुए 1 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक एक महीने का मिशन जरुरत मंद को कंबल गर्म कपड़े और खाने की व्यवस्था कराई जाएगी रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे रात तक संस्था के नौजवान टहलकर जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते रहेंगे ताकि ठंड की वजह से किसी की मृत्यु ना हो इस मौके पर डॉ मोहतशम रज़ा हैदर नक़वी अली जाफरी दिलशाद हुसैन फजल रिज़वी नुरुल हसन इमरान हुसैन नायब हैदर सफ़दर.हसनैन गोलू अफ़रोज़ हैदर रमीज़ अब्बास अकबर रज़ा आदि लोग मौजूद रहे। यह जानकारी शियाने हैदर ए कर्रार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अलमदार हुसैन ने दी।

अनियंत्रित डंपर ने अधेड़ को रौंदा

सुल्तानपुर। भोर में दुकान पर जा रहे अधेड़ को अवैध खनन में लगी अनियंत्रित डंपर रौंद कर फरार हो गई। जिससे अधेड़ की घटना स्थल पर मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पहुंचे नाराज परिजन शव नही उठाने पर अड़ गए। सूचना पर पहुंचे एस डी एम व सीओ के समझाने बुझाने तथा कार्यवाही के आश्वासन के बाद शव को मर्चरी भेजकर कार्यवाही की गई रविवार को भोर में नगर कोतवाली के रामनगर चौकी क्षेत्र के पल्हीपुर लाला का पुरवा गांव निवासी सतनाम(50) पुत्र बैजनाथ अपनी दुकान पर जा रहे थे।तभी रास्ते पीछे से आ रही अवैध खनन में लगी डंपर ने पल्हीपुर पैगापुर मार्ग पर पैगापुर गांव के पास रौंदते हुए फरार हो घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने साथ काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। परिजनों ने कहा कि पहले पुलिस कार्यवाही करे उसके बाद शव उठाया जाएगा। जानकारी मिलते ही नगर कोतवाल नारद मुनि सिंह के साथ सीओ सिटी प्रशांत सिंह, एस डी एम सदर विपिन द्विवेदी के साथ कुड़वार प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान वर्मा, बंधुआ कला विजय सिंह, धम्मौर ज्ञान चंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे।काफी देर मान मनौवल व दुर्घटना करने वाले डंपर पर कार्यवाही के साथ रात में होने वाले अवैध खनन पर लगाम लगाने के आश्वाशन के बाद परिजन शांत हुए।जिसके बाद नगर कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।नगर कोतवाल ने बताया कि परिजनो की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिये वाहनो पर लगाये रेडियम टेप

सुल्तानपुर। कटका क्लब सामाजिक संस्था के द्वारा जिले में अनोखी पहल की गई है, कर सेवा समाज की मिलता हमें सुकून। दुर्घटना न घटने दूं मेरा यही जुनून।। इन पंक्तियों को आत्मसात करते हुए कटका क्लब की टीम ने यातायात से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु बैटरी और ऑटो व वाहनों के आगे और पीछे रेडियम टेप लगाए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष सौरभ मिश्रा विनम्र ने किया और उन्होंने बताया कि इस समय पूरे जनपद के अंदर में शाम होते ही घना कोहरा जिले में पड़ रहा है। जिससे दुर्घटना ना हो सके इसलिए रेडियम टेप वाहनों की आगे पीछे लगाए जा रहे हैं। हादसे रोकने को सभी जरूरी उपायों को लेकर चालकों को जागरूक किया जा रहा है।सभी वाहनों के रेडियम टेप खुद से लगवा लेने की अपील की जा रही है। रेडियम टेप वाहन के आगे और पीछे लगे होने से रात के समय पीछे आने वाले वाहन की हैड लाइट पड़ने से रेडियम टेप चमकने लगेगी और इससे पीछे आने वाला वाहन के चालक को यह पत चल जाएगा कि आगे कोई गाड़ी अथवा टेक्सी जा रही है। इससे टक्कर होने से बच जाएगी। सौरभ मिश्र विनम्र ने बताया है कि बीते दिनों केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में एक लाख से ज्यादा हुई दुर्घटना को लेकर चिंता जाहिर की है जिसको लेकर संस्था विभिन्न अभियान चला रही है दुर्घटना को रोकने के लिए। इस अभियान राजकुमार मिश्रा, सर्वेशकांत वर्मा, शीतला प्रसाद पांडेय, कांति सिंह, मोनू यादव, वीर विक्रम सिंह, सूरज विश्वास, सुधांशु तिवारी ,अंकित तिवारी, नफीसा खातून के सहयोग से चल रहा है। जो 15 जनवरी तक निरंतर चलेगा। इस अवसर पर फूलचंद गौड़, शुभम, दीपक, किशन आदि लोग उपस्थित रहे।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़। सरायमीर थाने की पुलिस ने दुष्कर्म का 01 आरोपी किया गिरफ्तार, वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की पुत्री घर के बाहर बने बाथरूम में जा रही थी जहाँ पहले से घात लगाकर बैठा परविन्द उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 रामआसरे निवासी नरईपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी जिसका विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-657/2024 धारा 352,351(2)/75 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में पीड़िता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी। रविवार को व030नि0 धर्मेन्द्र कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त परविन्द उर्फ पिन्टू पुत्र रामाश्रय निवासी नरईपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष को नरईपुल के पास समय करीब 14.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

जानलेवा हमला करने वाला एक गिरफ्तार

आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाला एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में तथा जानलेवा हमले के लिए उकसाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वादी हरेन्द्र यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी ग्राम मण्डनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया दिनांक 03-01-2025 की शाम लगभग 7.30 बजे वादी की पत्नी सुभावती देवी हमारे पुराने घर मे चौकी पर लेटी थी तभी वादी का सगा भतीजा जो नाबालिग है द्वारा वादी के गाँव के छब्बू मिश्रा पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मण्डनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के सहपर वादी की पत्नी को जान से मारने की नियत से ईंट लेकर उसके सिर पर लगातार मारने लगा और उसका गला दबाने लगा जिससे उसके सिर में काफी गम्भीर चोट आ गयी तब वह वहाँ से भाग गया । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 07/2025 धारा 333/125/109/61(2) ठछै थाना अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

पिकअप की टक्कर पलटा अप्पे

सिराथू (कौशाम्बी)। कड़ा धाम थाना क्षेत्र के गौसपुर नवावा के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से गेहूं लदा अप्पे पलट गया , हादसे में अप्पे सवार दो लोग जख्मी हो गए स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को कड़ा के सरकारी अस्पताल के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया।सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बे के रहने वाले अंसार अहमद पुत्र असगर अली 52 वर्ष व सदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज निवासी मो समीर पुत्र अती उल्ला 34 वर्ष के साथ मंगलवार को अप्पे में गेहूं लादकर अलीपुर जीता की ओर जा रहे थे , अप्पे चालक जैसे ही कड़ा धाम थाना क्षेत्र के गौसपुर नवावा के पास पहुंचा तभी अलीपुर [illegible]

धूमधाम से मनाई गई वीर एकलव्य जयंती

आजमगढ़। वीर एकलव्य की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। एकलव्य नगर से भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें महिला पुरुष तथा छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में तीर धनुष मौजूद रहा। झांकी में ईष्टदेव वीर एकलव्य समेत विभिन्न महापुरुषों,फूलन देवी के चित्रों को सजाया गया था। नगर में निकली वीर एकलव्य की भव्य शोभायात्रा आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का आयोजन धर्मेंद्र निषाद डॉ0 राजू द्वारा एकलव्य नगर में आयोजित किया गया, जहां उपस्थित लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीर एकलव्य को याद किया। कार्यक्रम में वीर एकलव्य की झांकी भव्य रथ पर सजाई गई थी जिसके पीछे चल रहे बच्चों के हाथों में तीर धनुष सुशोभित हो रहा था, वहीं महिलाएं गीत गा रही थी तो डीजे की ध्वनि पर बच्चे थिरकते रहे। यह शोभा यात्रा एकलव्य नगर से खानपुर फतेह, रोडवेज, स्टेट बैंक, बुधनिया रोड, गोला बाजार, बरन चौक, दुर्गा मंदिर, बब्बर चौक, केसरी चौक समेत पूरे नगर पंचायत का भ्रमण करते हुए पुनः एकलव्य नगर में संपन्न हुई। सुरक्षा के दृष्टि से उप निरीक्षक संतोष कुमार,महिला उपनिरीक्षक समेत पुलिसकर्मी व महिला कांस्टेबल तैनात रहे। कार्यक्रम के आयोजक डॉ0 धर्मेंद्र निषाद राजू ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि आज हमें अपने महापुरुष वीर एकलव्य की जयंती पर उन्हें याद कर बेहद खुशी महसूस हो रही है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने वीर एकलव्य की झांकी निकाली है जो 5 जनवरी को प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन मनाते हैं और एक विशाल झांकी निकालते हैं। हम लोग इस जयंती को 16 वर्षों से मना रहे हैं जो कि प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या बढ़ती ही जाती है। निषाद परिवार एक उत्सव के रूप में इसे मानता है सिर्फ अतरौलिया ही नहीं अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं इसमें निषाद समुदाय के संत व महात्मा लोग भी उपस्थित होते हैं। जिन लोगों ने अपने इतिहास को नहीं जाना वह जातियां मिट गई, इसलिए हम लोग अपने वंशजों को याद करते हैं। महात्मा ने कहा कि महान धनुर्धर वीर एकलव्य जी हिरण धनु के पुत्र हैं जिन्हें वीर धनुर्धर द्वारकाधीश वीर एकलव्य के नाम से भी जाना जाता है।

डीएम ने शिकायतकर्ताओं की सुनी समस्याएं

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता सुनवाई के दौरान दूर-दराज से आये हुये फरियादियों की शिकायतों को गम्भीरतापूर्वक सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों

➤ शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करायें-जिलाधिकारी

कारियों को प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। शिकायतकर्ता नैमुननिशा निवासी मवैयाकला थाना अन्तू ने शिकायत किया कि भूमि गाटा संख्या-87ग जो आबादी के खाते में दर्ज है जिसमें प्रार्थिनी का पूर्वजीय मकान, दीवाल, छप्पर आदि बिना है, प्रार्थिनी पीढ़ी पर पीढ़ी आबादी के रूप में प्रयोग करती चली आ रही है परन्तु गांव के ही नौशाद, हकीम, सगीर व जमील रास्ता के लिये झूठा प्रार्थना पत्र देकर प्रार्थिनी की आठ फिट ऊंची बनी दीवाल को तोड़कर रास्ता बनाना चाह रहे है जबकि पुराना रास्ता मौजूद है परन्तु उधर से उक्त लोग रास्ता बनाने नहीं दे रहे है, पुराने रास्ते पर कोई निर्माण नहीं है, रास्ता मौजूद है परन्तु उक्त लोग पुराने रास्ते पर कब्जा कर रहे है, रास्ता नही बनने

दे रहे है। पुराने रास्ते को लेकर गांव के दो पक्षों में विवाद भी हो चुका है परन्तु उक्त लोग सरहंगई के बल पर पुराने रास्ते को जबरन अवरूद्ध कर रहे है व प्रार्थिनी के सहन दरवाजे पर बनी पक्की बाउण्ड्रीवाल तोड़कर रास्ता बनाना चाह रहे है, झूठा प्रार्थना पत्र देकर परेशान कर रहे है, इस प्रकरण पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सदर एवं एसएचओ अन्तू को निर्देशित किया है कि संयुक्त टीम बनाकर जांच करायें एवं आवश्यक कार्यवाही करें, अनाधिकार रास्ता आदि न बनाया जाये एवं मौके पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करायें। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त राजस्व शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच कर, शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से करें जिससे शिकायतकर्ता को इधर-उधर भटकना न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें, कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे इसका विशेष ध्यान दें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनता की शिकायतों को शासन की मंशानुरूप गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ससमय करायें, शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही कदापि न बरती जाये।

जयंती पर किया गया योगदान पर विमर्श

बस्ती (आरएनएस)। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति और कबीर साहित्य सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में महारानी लक्ष्मीबाई और पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्व. इंदिरा गांधी को जयंती पर शिद्दत से याद किया गया।मुख्य अतिथि डा. वीके वर्मा ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की परिस्थितियां भले ही भिन्न थी लेकिन दोनों का मूल उद्देश्य समर्थ और शक्तिशाली भारत का निर्माण करना था। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी ने देश को नई दिशा दी। दोनो स्त्री शक्ति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वरिष्ठ साहित्यकार डा. राम कृष्णलाल जगमग ने कविताओं के माध्यम से दोनों वीरांगनाओं को नमन किया। बी.के. मिश्र, पं. सदानन्द शर्मा ने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई और पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने अपने-अपने समय में देश को कई संकटों से उबारते हुये देश हित में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अध्यक्षता करते हुये बटुकनाथ शुक्ल ने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई और पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का योगदान सदैव याद किया जायेगा। अजमत अली एडवोकेट, ताहिर अली, चन्द्रमोहन लाल श्रीवास्तव, दीनानाथ यादव, मो. सामईन फारूकी, गणेश प्रसाद, नेबूलाल, पं. आदि ने महारानी लक्ष्मीबाई और पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्व. इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य रूप से नन्दलाल यादव, ओम प्रकाश धर द्विवेदी, आचार्य छोटेलाल वर्मा, मेहीलाल यादव, गणेश मौर्य, दीनानाथ यादव, कृष्ण कुमार सिंह, कृष्णचन्द्र पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

कागज पर बना आवास लाभार्थी के खाते में नही पहुंची फूटी कौड़ी

कौशाम्बी। विकास खंड सिराथू के केशवपुर गांव की एक महिला का इंदिरा आवास कागज पर बन गया। जबकि महिला लाभार्थी का दावा है कि बैंक खाते में फूटी कौडी नही पहुंची है। प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन करने पर पूर्व में कलोनी मिलने की जानकारी हुई। महिला की शिकायत पर डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बीडीओ भवेश कुमार शुक्ला को जांच करने का निर्देश दिया है। गरीबों को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। चयनित लाभार्थी के बैंक खाते में एक लाख बीस हजार प्रोत्साहन राशि व उन्नीस हजार मनरेगा से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। शासन के निर्देश पर पात्रों को योजना का लाभ देने के लिए सर्वे कर सूची तैयार कराई जा रही है। देवखर गांव निवासी मोहम्मद एहसान का परिवार कच्चे घर रहता है। एक माह पहले पत्नी रुकसाना ने डीएम पोर्टल पर प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था। जिस पर जांच करने उसके घर अधिकारी पहुंचे और जिओ ट्रैकिंग करने के दौरान पता चला कि वर्ष 2014 व 15 में उसे इंदिरा आवास योजना के तहत 70 हजार की किस्त खाते में भेजी गई है। इतना सुनकर रुखसाना के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसके खाते में पैसे नहीं आए हैं ना ही उसका आवास बना है।

मण्डलायुक्त ने की समीक्षा बैठक

सोनभद्र। रोल आब्जर्वर/आयुक्त विंध्याचल मण्डल मीरजापुर डॉ मुथुकुमार स्वामी बी ने मंगलवार को सर्किट हाउस में विधानसभा मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में तृतीय भ्रमण के दौरान अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चेकलिस्ट के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक किये। इस दौरान रोल आब्जर्वर ने पूर्व के बैठक/भ्रमण के मौके पर बूथों पर मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम घटाने व नाम में संशोधन करने के निर्देश दिए गए थे, के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता व पारदर्शिता की बारी बारी से समीक्षा किये। बैठक में रोल आब्जर्वर/आयुक्त विंध्याचल मण्डल मीरजापुर ने विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 में विधानसभा वार प्राप्त दावें और आपत्तियां, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 के दौरान आलेख्य प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन में मतदाताओं, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 के दौरान मतदाता, जेण्डर रेशियो, एवं 18-19 आयुवर्ग के मतदाताओं, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 के दौरान दिव्यांग मतदाताओं एवं अति अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी0आई0पी0) मतदाताओं, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के दौरान प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण, फार्मेट 1-8 तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र आदि बिन्दुओं पर बारी-बारी से समीक्षा किये। उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बूथों पर स्थलीय निरीक्षण में प्राप्त फार्म 6, 7 व 8 पर किये गए जाँच/निरीक्षण के गुणवत्ता की जाँच किये। उन्होंने सम्बन्धितों को निर्देशित करते हुए कहा कि फार्म-7 से प्राप्त आवेदनों का स्थलीय निरीक्षण अवश्य किया जाये और निस्तारण करते समय टिप्पणी अवश्य दर्ज की जाये, जिससे पता चल सके कि किस कारण से नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। आयोग के मानक के अनुरूप जेण्डर रेशियो को बढ़ाने के निर्देश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिये।

छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़। मेंहनाजपुर:-किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की उम्र 17 साल 6 माह है। दिनांक 03.01.25 को समय 08.00 बजे सुबह वादिनी अपने घर से कोचिंग पढ़ाने जा रही थी कि रास्ते में अभियुक्त रिपुल जैसवार पुत्र सुबास जैसवार ग्राम नरायनपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर जो अपने बुआ के घर रह रहा है द्वारा वादिनी की साइकिल को रास्ते मे रोककर वादिनी के साथ बतमीजी भरी बातें करने लगा तथा छेड़खानी करने लगा। जिसका विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा वादिनी व उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गयी।

जन्म प्रमाणपत्र की प्रक्रिया होगी सरल: डीएम

जौनपुर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र सिंह से मुलाकात कर उन्हें शिक्षकों के समस्याओं से अवगत कराया साथ ही जनपद के परिषदीय विद्यालय के बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में उनके अभिभावकों को जो अत्यंत ही कठिनाई का सामना कर करना पड़ रहा है उसके बारे में भी जिलाधिकारी को अवगत कराया। बताया कि आफिसों का चक्कर लगाने के साथ ही उनका आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है और जन्म प्रमाण पत्र समय से उपलब्ध न होने के कारण आधार नहीं बन पा रहा है और आधार न बनने के कारण परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी समय से नहीं हो पा रहा है।अमित सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी के लिए विभाग द्वारा आधार आवश्यक कर दिया गया है और आधार बनवाने के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। आधार बनवाने के लिए पहले विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित जन्मतिथि पर भी आधार बन जाता था जिससे अभिभावकों को इसके लिए दौड़ भाग नहीं करना पड़ता था लेकिन अब ब्लाकध्यायक्ष विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र को आवश्यक कर दिया गया है इसके लिए अभिभावकों को ब्लाक का चक्कर काटना पड़ता है और समय से जन्मप्रमाण पत्र नहीं मिल पाता जिसके आभाव में डीबीटी से बच्चे वंचित रह जाते हैं।जिलाधिकारी ने उक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व संगठन से परिषदीय विद्यालयों के जिन बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र नही बना है उन बच्चों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा।

महाकुम्भ को स्वच्छ और पॉलिथिन मुक्त रखने हेतु

दुकान जी ने स्लोगन लिखे परिधान पहनकर जागरुक किया। उन्होंने संदेश दिया कि गंगा नदी को प्रदूषण दूर करने हेतु उसमें माला, फूल, हवन न डाले।

वृद्धाश्रम में सेवार्थ कार्य

प्रयागराज। भारत विकास परिषद कालिंदी शाखा द्वारा अटल बिहारी

वाजपेई नगर स्थित देवनारायण आनंद वृद्धाश्रम में भोजन मंत्र के साथ बृद्धो को भोजन ग्रहण कराया। कार्यकम में प्रांतीय मीडिया प्रभारी मनीष सिंह, सचिव आर पी शर्मा, कार्यक्रम में शाखा के अध्यक्ष प्रदीप चक्रवर्ती ,उपाध यक्ष संपर्क वीरेश्वर बनर्जी, उपाध्यक्ष संस्कार सचिन जायसवाल ,सचिव आर पी शर्मा,सह सचिव राजेश कुमार जायसवाल, महिला संयोजिका मिथिलेश जायसवाल , संगठन सचिव सोनाली मिश्रा एवं वरिष्ठ सदस्य पुतुल बनर्जी , रजनी शर्मा तथा गीता कुलश्रेष्ठ, महिला संयोजिका मिथिलेश जायसवाल उपस्थित रहे।

पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक कैसे आएंगे

प्रयागराज। जो भी पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक कैसे मिलेंगे? रसायन विज्ञान से डर लगता है, क्या करें? ऐसे ही कई सवालों और समस्याएं सोमवार से शुरू हुई यूपी बोर्ड की हेल्प डेस्क के सामने आईं। दिनभर टोल फ्री नंबर वाले फोन घनघनाते रहे। 37 परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों ने हेल्प डेस्क से संपर्क किया। फोन पर ही परीक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया गया। यूपी बोर्ड कार्यालय में शुरू हुई हेल्प डेस्क 12 मार्च को परीक्षा के आखिरी दिन तक सक्रिय रहेगी। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी, ऐसे में परीक्षार्थियों के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए डेढ़ माह का वक्त है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के निर्देश पर हेल्प डेस्क का संचालन अभी से इसीलिए शुरू किया गया है, ताकि परीक्षार्थियों को तैयारी में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रयागराज के अतुल कुशवाहा ने बताया, जो पढ़ते हैं, वह भूल जाते हैं। काउंसलर ने उन्हें सलाह दी कि प्रश्न के उत्तर को बार–बार लिखकर याद करें। मैनपुरी की 12वीं की छात्रा दीक्षा ने कहा, 'रसायन विज्ञान में बहुत डर लगता है, क्या करें?'। जवाब मिला कि नर्वस न हों और अपने शिक्षक से मिलें। उन्हें अपनी समस्याएं बताएं, वह मदद करेंगे। दीक्षा ने काउंसर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपसे बात करके मन हल्का हो गया। अब लग रहा है कि तैयारी अच्छे से हो जाएगी। औरैया से पीयूष ने पूछा कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं। जवाब मिला कि लिखकर याद करें और की–प्वाइंट जरूर बनाएं। मेरठ से जुनैद का सवाल था कि क्या इस बार प्रश्न सिलेबस के बाहर से पूछे जाएंगे। बताया गया कि ऐसा नहीं होगा, प्रश्न सिलेबस से ही आएंगे। गोरखपुर से 12वीं के छात्र प्रवीण ने बताया, हाईस्कूल के सर्टिफिकेट में पिता का नाम गलत दर्ज हो गया है। उन्हें बताया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें। ज्यादातर विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी विषय की तैयारी के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट नचउेच.मकन.पद पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए 19 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, 20 लाख पहुंचने की उम्मीद

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 19 लाख से ऊपर पहुंच गई है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा–2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के कारण ओटीआर की संख्या तेजी से बढ़ी है। यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा में आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य है। ओटीआर नंबर प्राप्त किए बिना अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से पहले ओटीआर की संख्या 18.86 लाख के आसपास थी।

उत्तर मध्य रेलवे

ई-टेन्डर नं0: पीआरवाईजे-सिग-038-2024-25 दिनांक: 03.01.2025

ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूर संचार अभियन्ता/समन्वय/उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एंव उनकी ओर से निम्नलिखित निर्धारित कार्य के लिये ई- निविदा निर्धारित प्रपत्र पर **दिनांक 27.01.2025 को 12.00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है। **कार्य का विवरण निम्न प्रकार है।**

कार्य का विवरण: प्रयागराज मण्डल के प्रयागराज छिवकी सूबेदारगंज एवं नैनी स्टेशन पर आइपी टेलीफोन एक्सचेंज (मैसर्स अल्काटेल मेक) का कोडल लाइफ के छह वर्षो के लिए काम्प्रहेन्सिव वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध।

अनुमानित मूल्य (₹) : ₹ 18,21,310.74	**बिड सिक्योरिटी (₹) :** ₹ 36,400/-
निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹) : ₹ 0.00	**कार्य समापन की अवधि:** 72 माह

निविदा बन्द होने की तिथि : 27.01.2025

निविदा प्रपत्रों की उपलब्धता: निविदा प्रपत्र **www.ireps.gov.in** पर निविदा खुलने की तिथि से 21 दिन पहले उपलब्ध हो जायेंगें। **बयाने की राशि जमा करना एवं उसका रूप:** निविदाओं को उपरोक्त बिड सिक्योरीटी निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन भुगतान गेटवे द्वारा की जायेगी। यदि निविदा दाता बिड सिक्योरीटी उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में जीसीसी के अनुसार जमा करते हैं तो उनका निविदा स्वीकार किया जायेगा। यदि निविदादाता द्वारा जमा की गयी बिड सिक्योरीटी बैंक गारंटी के रूप में है तो यह उचित स्टांप शुल्क के अनुसार होना चाहिये। बैंक गारंटी जमा करते समय यह 30प्र0 स्टांप अधिनियम 2008 की धारा 13 एवं 24 और समय - समय पर निर्धारित दर के अनुसार होना चाहिये। बिना बिड सिक्योरीटी वाली निविदायें खारिज कर दी जायेंगी। **निविदा खुलने का समय, तिथि तथा स्थान:** निविदा पूर्व निर्धारित तिथि को 12.30 बजे या उसके बाद ई-निविदा द्वारा मण्डल रेल प्रबंधक, प्रयागराज के कार्यालय में खोली जायेगी। अगर उस दिन किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहे तो निविदा अगले दिन, कार्य दिवस पर खोली जायेगी। **निविदा की वैधता:** निविदा खुलने के 60 दिन तक। **निविदा डीलिंग हेतु रेलवे के अधिकार:** रेलवे प्रशासन का किसी भी समय बिना कारण बताये कोई एक या सारी निविदाओं को स्थगित/संशोधित/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। 30/25(A)

f North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

एनसीआरः महाकुंभ में निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण कदम

प्रयागराज। महाकुंभ मेला में प्रयागराज, सुबेदारगंज, प्रयागराज छिवकी, नैनी, विन्ध्याचल, भरतकूप, शिवरामपुर, चित्रकूट धाम कर्वी इत्यादि स्थानों पर रेगुलर सप्लाई के साथ साथ ओ एच ई (व्अमत भ्मंक स्समबजतपपिबंजपवद) द्वारा ऑक्जीलरी ट्रॉन्सफार्मर को दी जा रही निर्बाध विद्युत आपूर्ति को भी विस्तारित करते हुए दिया गया है जिससे इन स्थानों पर हमेशा विद्युत आपूर्ति बनी रहेगी।

इसके अतिरिक्तनिर्बाध प्रकाश व्यवस्था और बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए–

स्टेशन प्लेटफॉर्म एवं परिसर में 3000 नग रिचार्जेबल ट्यूबलाइट की व्यवस्था की गई है

उपरोक्त व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सभी स्थानों पर 20 नग ऑक्जीलरी ट्रॉन्सफार्मर लगाए गए

स्टेशनों पर 16 नग अतिरिक्त डीजल जनरेटर (डी.जी.) सेट सेवा देने हेतु लगाए गए

14 नग यू पी एस (Uninterruptible Power Supply) लगाये गए हैद्य

उपरोक्त व्यवस्थाएं इमरजेंसी परिस्थिति में कार्य करेगी जिससे स्टेशनों पर अँधेरा नहीं होगा एवं यात्रियों का सामान्य रूप से आवागमन बाधित नहीं होगा द्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विद्युत आपूर्ति के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों को चोबीसो घंटो के लिए रेलवे कर्मचारी लगाये गए है, जो कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु निरंतर अपनी पैनी नजर रखेंगे द्य स्टेशन पर पैदल पुलों एवं सीढियों पर विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है।

यात्रियों को विद्युत आघात से सुरक्षा प्रदान के लिए

934 नग अर्थिंग की जांच की गई जो एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा,

इसके अतिरिक्त 374 स्थानों पर अर्थिंग की थर्मो विजन कैमरा से जांच की गई है

स्टेशनों पर 866 नग आर सी बी ओ (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection) लगाये गए है। ये यात्री द्वारा विद्युत आपूर्ति उपकरणों को टच करने की अवस्था में तुरंत ही विद्युत आपूर्ति को बंद कर देगा एवं यात्रियों को विद्युत आघात से सुरक्षा प्रदान करेगा।

सुरक्षा के साथ विद्युत् आपूर्ति निरंतर जारी रह सके इसके लिए विद्युत सामान्य विभाग द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु विगत कई महीनो से एक ड्राइव चला कर हर एक विद्युत आपूर्ति बिन्दुओ को चिह्नित कर उनके सेफ्टी को जांचा परखा गया है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके द्य

जैसे–जैसे मेला नजदीक आ रहा है , विद्युत सामान्य विभाग की टीम दिन–रात कार्य कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं का आध्यात्मिक अनुभव उनकी यात्रा के अनुभव के समान सहज, सरल और निर्बाध हो। भारतीय रेलवे एक बार फिर अपने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए महाकुंभ मेला 2025 के इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

डीएफसीसीआईएल में हितधारकों के साथ बैठक की

प्रयागराज। कानपुर में डीएफसीसीआईएल और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ बैठक की। बैठक में व्यापार मॉडल के विकास तथा समग्र अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को समझने के लिए इस बैठक में भाग लिया। डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली के बिजनेस डेवलपमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स के समूह महाप्रबंधक एस पी वर्मा ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय प्रबंधक अंशुल कटारिया की उपस्थिति में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मेसर्स कृति पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स

सिंह कंस्ट्रक्शन, मेसर्स रुद्र कंस्ट्रक्शन, मेसर्स हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कानपुर लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स देवी मां शक्ति लिमिटेड, मेसर्स चरण फ्लोर मिल्स, मेसर्स यूजीआर साइलोज हमीरपुर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पीएमसी सर्विसेज, मेसर्स विकल्प कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जीएस तिवारी एंड कंपनी, मेसर्स इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मेसर्स कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेसर्स जगमोहन लॉजिस्टिक, मेसर्स यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मेसर्स कैटमैक्स मल्टीमैक्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में व्यापार को बढ़ावा देने और रेलवे परिवहन प्रणाली में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) और साइडिंग के लाभों को दर्शाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जीसीटी के लाभों पर भी चर्चा की गई। इनमें शामिल हैं– गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) माल ढुलाई के लिए वाणिज्यिक सुविधाएं हैं जिन्हें राजस्व बढ़ाने और माल ढुलाई संचालन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। अतिरिक्त टर्मिनलों के विकास में उद्योग निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दिसंबर 2021 में गति शक्ति मल्टी–मॉडल कार्गो टर्मिनल (GCT) नीति शुरू की गई थी।

जीसीटी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैंरू

स्थानरू जीसीटी का स्थान कार्गो यातायात की संभावना और उद्योग की मांग के आधार पर तय किया जाता है।

आवेदन प्रक्रियारू जीसीटी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि त्वरित और परेशानी मुक्त मंजूरी मिल सके।

कोई विभागीय शुल्क नहींरू आवेदकों के लिए कोई विभागीय शुल्क नहीं है।

कोई भूमि लाइसेंस शुल्क नहींरू कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेलवे भूमि के लिए कोई भूमि लाइसेंस शुल्क नहीं है।

हैंडलिंग अधिकाररू जीसीटीओ के पास विशेष हैंडलिंग अधिकार हैं और वे हैंडलिंग शुल्क या शुल्क ले सकते हैं।

सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाएंरू रेलवे सेवारत स्टेशन पर सभी सामान्य–उपयोगकर्ता यातायात सुविधाओं की पूंजीगत लागत के लिए जिम्मेदार है।

"गैर–रेलवे भूमि पर जीसीटी टर्मिनल (अनुसूची '1') आवेदन के आधार पर और

पूरी तरहध्आंशिक रूप से आईआर भूमि पर जीसीटी टर्मिनल (अनुसूची '2') व्यमद ज्मदकमत द्वारा"

प्रतिष्ठित पक्षों द्वारा ट्रक ऑन ट्रेन (टीओटी) सेवाओं में रुचि दर्शाई गई है। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव श्री मनीष कटारिया ने भी कानपुर में 18 मीटर बीआरएन वैगन उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता की जांच करने का अनुरोध किया है ताकि ट्रक ऑन ट्रेन सेवाएं शुरू की जा सकें। इसके अलावा, मेसर्स यूजीसी सिलोस हमीरपुर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री यश एन उपाध्याय ने ट्रक ऑन ट्रेन सेवाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं।

ष्ट्रक ऑन ट्रेन सेवा डीएफसीसीआईएल की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख सेवा है जो वर्तमान में न्यू पालनपुर से न्यू रेवाड़ी जंक्शन के बीच चल रही है। इससे एक तरफ से एक रेक में 45 ट्रकों को उतारने की सुविधा मिलती है और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है और एक वरदान के रूप में यह पर्यावरण अनुकूल सेवा है जो सड़क से ट्रकों को उतारने के अलावा ईंधन और समय की भी बचत करती है। वैगन टर्न राउंड की सभी ने खूब सराहना की और गहरी दिलचस्पी दिखाई।ष्

यूपीएसआईडीए के क्षेत्रीय प्रबंधक ने डीएफसीसीआईएल स्टेशनों को जोड़ने वाली साइडिंग के लिए सब्सिडी प्रदान करने पर भी चर्चा की।

बैठक का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ तथा डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों ने हितधारकों द्वारा दिखाई गई प्रतिक्रिया की सराहना की तथा रेल परिवहन में एक नए हितधारक के रूप में डीएफसीसीआईएल के साथ जुड़ने में उनकी गहरी रुचि का स्वागत किया। बैठक में प्रयागराज पश्चिम के मुख्य महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह, महाप्रबंधक (सुरक्षा) आशीष मिश्रा, प्रयागराज के अपर महाप्रबंधक (ओपी एवं बीडी) मन्नू प्रकाश दुबे, कानपुर सेंट्रल के उप सीटीएम आशुतोष सिंह, प्रबंधक बीडी राजेश कुमार, एपीएम ओपी एवं बीडी उपेंद्र सिंह भदौरिया मौजूद रहे।

Dr. Sudha Malhotra was the oldest alumini of University of Allahabad who participated in Allumini Meet 2024.
Born on 28.12.1931
Died on 7.01.2025
Birth place : Jalandhar, Punjab
Family : unmarried, just had one sister who is no more
Reason of death: Burn
Took admission in University of Allahabad in 1952
Joined Department of Education, University of Allahabad as a Lecturer in 1962
Retired in 1992
Wrote 2 books and was associated with publication of a journal : Trends and Thoughts in Education

रुपए की वसूली की

प्रयागराज। जोन दो मुट्ठीगंज में वार्ड 80श 88, एवं 57 में कुर्की की कार्यवाही की गई जिसमें भवन संख्या 843/655। बहादुरगंज, अब्दुल हकीम व भवन संख्या 159/68 बलुआ घाट, शंकर लाल एव 1411/947 मुट्ठीगंज, विनोद कुमार के बकाये पर कर अधीक्षक श्रीमती जया सिंह के साथ राजस्व निरीक्षक सर्वेश कुमार एवं सौरभ कुमार, के द्वारा सीलिंग की वृहद कार्यवाही की गई व अन्य बकायेदारों से 459903 रुपए की वसूली की गई।

मृतक आश्रित को नियुक्तिपत्र मिला

प्रयागराज। नगर निगम में मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र मिला। जिसमें एक कनिष्ठ लिपिक, तीन चपरासी और एक सफाईकर्मी पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। उदय शंकर कुशवाहा, नेहा कश्यप, अभिषेक गुप्ता, प्रियांशु राज, सनोज कुमार को नियुक्ति मिला। पत्र को महापौर गणेश केसरवानी ने वितरित किया।

हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद सैनिक को अंतिम विदाई देने उमड़ी भीड़, रसूलाबाद घाट पर हुआ अंतिम संस्कार

प्रयागराज। गुजरात के पोरबंदर पोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए प्रयागराज में रहने वाले कमांडेंट सौरभ यादव (42) का शव मंगलवार को सेना के वाहन से गांव पहुंचा तो शहीद के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ गई। बड़ी संख्या में लोगों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। दोपहर बाद शव का अंतिम संस्कार शहीद के पैतृक गांव कौशाम्बी में किया गया। घाट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शव की अंत्येष्टि की गई। बता दें कि गुजरात के पोरबंदर पोर्ट पर हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए इंडियन कोस्टगार्ड के तीन सैनिकों में शहर के सपूत कमांडेंट सौरभ यादव (42) भी शामिल थे। मूलरूप से कौशाम्बी निवासी शहीद का परिवार धूमनगंज के साकेत नगर का रहने वाला है। कोस्टगार्ड की टीम मंगलवार को पार्थिव शरीर लेकर पहुंची। पहुंचेगी। इसके बाद रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद के मामा गजेंद्र यादव ने बताया कि रविवार दोपहर हुए हादसे की सूचना शाम को परिजनों को मिली। बताया गया कि मेडिकल रेस्क्यू के बाद पोर्ट पर लैंड करते वक्त हुए हेलिकॉप्टर क्रैश में सौरभ के साथ मौजूद उनके दो साथियों की मौके पर ही सांसें थम गई थीं। जबकि, गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल ले जाते वक्त सौरभ भी शहीद हो गए थे। मामा ने बताया कि सौरभ के पिता ज्ञान सिंह पुलिस विभाग में वित्त नियंत्रक पद से रिटायर हुए हैं। वह मूल रूप से कौशाम्बी के कोखराज स्थित अलीगंज के रहने वाले हैं। उनकी तीन संतानों में सौरभ मझले थे और 2022 से इंडियन कोस्टगार्ड में तैनात थे। उनकी तैनाती पोरबंदर में थी। जहां वह अपनी पत्नी वासिता व दो बच्चों छह वर्षीय बेटी टीका व तीन साल के बेटे बाली के साथ रहते थे। उन्होंने बताया कि सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद पोरबंदर में ही उन्हें अंतिम सलामी दी गई। सौरभ के छोटे भाई अंकुश अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जबकि, बड़ी बहन एचबीटीआई कानपुर में तैनात हैं।

पत्नी के आत्मसम्मान व गरिमा को चोट पहुंचाती है जबरन वेश्यावृत्ति, पति की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवविवाहिता पत्नी को दोस्तों संग संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के आरोपी पति को जमानत देने से इन्कार कर दिया। कहा कि यह महज दंपती के बीच साधारण वैवाहिक विवाद नहीं, बल्कि एक पत्नी के आत्मसम्मान और गरिमा को चोट पहुंचाने वाला मामला है। पीड़िता शारीरिक चोट के साथ ही ऐसे दर्दनाक अनुभव बर्दाश्त करती है, जो आजीवन उसकी आत्मा को कचोटता रहेगा। लिहाजा, आरोपी को जमानत नहीं दे सकते। की। मामला अलीगढ़ के कवारसी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने 17 जून 2024 को अपने दामाद सलमान के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, सामूहिक दुष्कर्म कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। तहरीर में बताया कि बेटी का निकाह फरवरी 2024 में किया था। निकाह के बाद पता चला कि दामाद वेश्यावृत्ति जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़ा है।

सम्पादक
सिद्धनाथ द्विवेदी
प्रबन्धक निदेशक
दीपक जयसवाल
सम्पादकीय कार्यालय
11ई/2, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के आधीन होगा।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक सिद्धनाथ द्विवेदी द्वारा काम्पीटेंट बिजनेस सर्विसेज विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित एवं 399 कृष्णानगर कीडगंज से प्रकाशित।
सम्पादक–सिद्धनाथ द्विवेदी, आरएनआई नं. UPHIN/2007/22706 रजि.नं. AD-32/2008-09 ईमेलः amritkt.alld@gmail.com फोन नं. : 9453273951, 8799627062